

भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन रहा है

16 जून, 2025

प्रमुख बातें

- भारत 2022 में 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत घरेलू सुधारों और वैश्विक स्थिति से प्रेरित है।
- भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसमें वास्तविक जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ रही है और सांकेतिक जीडीपी 106.57 लाख करोड़ रुपये (2014-15) से तीन गुना बढ़कर 331.03 लाख करोड़ रुपये (2024-25) हो गई है।
- भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था (2025-26 में 6.3% से 6.8%) होने का अनुमान है।
- पिछले दशक में कुल निर्यात में 76% की वृद्धि हुई, जो 2024-25 में 825 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स का योगदान रहा।
- सेवाओं का निर्यात दोगुना से भी ज़्यादा हुआ, जो 2013-14 में 158 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 387 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- संचयी एफडीआई प्रवाह 1.05 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें अकेले वित्त वर्ष 25 के पहले 9 महीनों में इक्विटी प्रवाह में रिकॉर्ड 27% की वृद्धि हुई।
- डिजिटल लेन-देन की मात्रा में 9 गुना वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 18-वित्त वर्ष 24), जिसमें अकेले 2024 में यूपीआई द्वारा 172 बिलियन लेनदेन संसाधित किए गए।
- लक्षित राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति को औसतन 8.2% (2004-14) से घटाकर लगभग 5% (2015-25) कर दिया गया।
- खुदरा मुद्रास्फीति 2024-25 में गिरकर 4.6% हो गई, जो 2018-19 के बाद सबसे कम है।

परिचय

भारत, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है और 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर के अनुमानित जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था (2025-26 में 6.3% से 6.8%) बनने का अनुमान है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक दशक के निर्णायक शासन, दूरदर्शी सुधारों और वैश्विक जुड़ाव का परिणाम है। मजबूत घरेलू मांग, एक गतिशील जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और निरंतर आर्थिक सुधारों से प्रेरित होकर, भारत वैश्विक व्यापार, निवेश और नवाचार में अपने बढ़ते प्रभाव का दावा कर रहा है।

कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने टिप्पणी की: "पुराने दिनों में, विश्व बैंक भारत को बताता था कि क्या करना है, लेकिन अब, भारत विश्व बैंक को बताता है कि क्या करना है।" यह कथन पिछले ग्यारह वर्षों में भारत के एक आश्रित अर्थव्यवस्था से एक आत्मनिर्भर, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी महाशक्ति में बदलाव को शक्तिशाली रूप से दर्शाता है।

इस परिवर्तन के मूल में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है, जो नवाचार, उद्यमशीलता और तकनीकी संप्रभुता को बढ़ावा देने वाला आंदोलन है। मोदी के नेतृत्व में, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं, एमएसएमई के पुनरोद्धार और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसी रणनीतिक पहलों ने उच्च-विकास, उच्च-अवसर वाली अर्थव्यवस्था की नींव रखी है।

इस विज़न का मुख्य उद्देश्य समावेशी और न्यायसंगत विकास है। सरकार की नीतियों ने रोजगार सृजन, छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन, सार्वजनिक

निवेश में वृद्धि और मध्यम वर्ग और उद्यमियों के वित्तीय सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आर्थिक प्रगति से हर नागरिक को लाभ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति केवल गति बनाने लिए न होकर, देश के आर्थिक भाग्य को नया आकार देने के लिए है। आज, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो डिजिटल, हरित, आकांक्षी और भविष्य के लिए तैयार है, जो वैश्विक नेता बनने के अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है।

त्वरित तथ्य

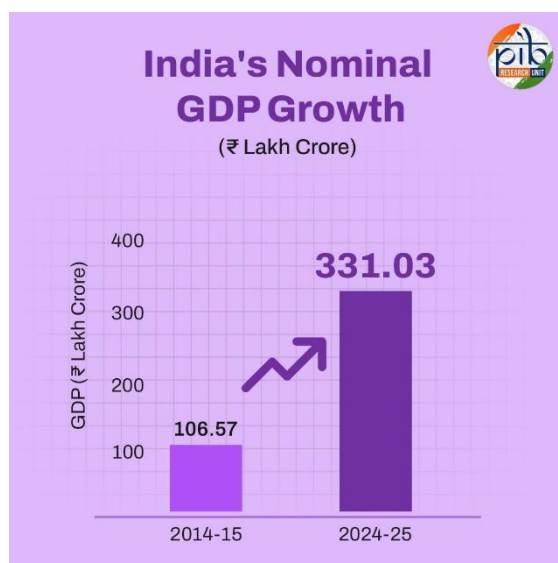
कोविड के दौरान 29.8 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने अर्थव्यवस्था को बचाया।

‘ग्रोथेड’ के लिए आधार तैयार करना

- भारतीय कॉरपोरेट्स ने 2024-25 में आईपीओ के माध्यम से 1,62,387 करोड़ रुपये की सर्वकालिक उच्च राशि जुटाई।
- राष्ट्रीय राजमार्ग 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर मार्च 2025 तक 1,46,204 किलोमीटर हो गए।
- देश में 160 परिचालन हवाई अड्डे हैं, जिनमें मार्च 2025 तक 145 हवाई अड्डे, 2 जल हवाई अड्डे और 13 हेलीपोर्ट शामिल हैं।
- नई विनिर्माण इकाइयों के लिए 2024 तक 15% कर दर का विस्तार, और स्टार्ट-अप के लिए कर प्रोत्साहन, उच्च-विकास क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे और रोजगार पैदा करेंगे।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल एनपीए दिसंबर 2024 में 12 साल के निचले स्तर 2.6% पर आ गया।

जीडीपी वृद्धि: आर्थिक आधार को मजबूत करना

पिछले दशक में भारत की जीडीपी में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। मौजूदा कीमतों पर, जीडीपी 2014-15 में 106.57 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में अनुमानित 331.03 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो कि केवल दस वर्षों में लगभग तीन गुना वृद्धि है। अकेले 2024-25 में, सांकेतिक जीडीपी पिछले



वर्ष की तुलना में 9.9% बढ़ी,

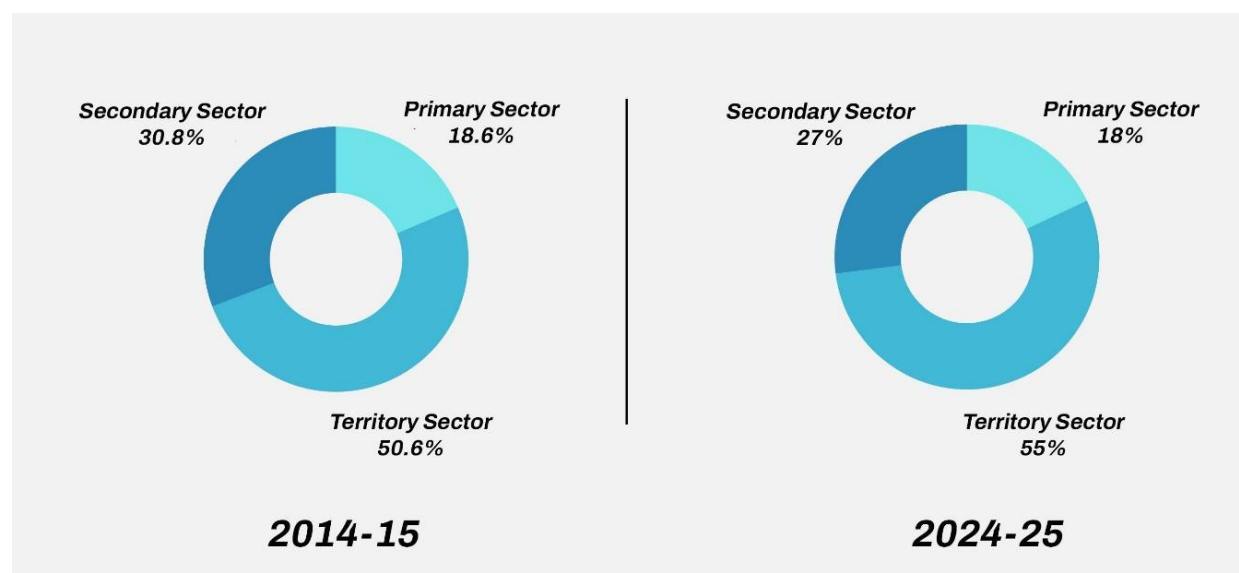
जबकि वास्तविक जीडीपी (स्थिर कीमतों पर) 6.5% बढ़ी, जो निरंतर आर्थिक गति को दर्शाती है। यह तीव्र वृद्धि देश के बढ़ते आर्थिक आधार और बढ़ते आय स्तरों को दर्शाती है।

इसी अवधि के दौरान वास्तविक जीवीए 6.4% और सांकेतिक जीवीए 9.5% बढ़ा। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में ग्रामीण मांग में सुधार के कारण 7.3% की

वृद्धि हुई, जो 2002-03 के बाद से जीडीपी (61.8%) में अपने उच्चतम हिस्से पर पहुंच गया। सेवा क्षेत्र जीवीए में सबसे स्थिर योगदानकर्ता बना हुआ है, जिसका अंश वित्त वर्ष 14 में 50.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में लगभग 55% हो गया है।

यह लगभग 30% कार्यबल को रोजगार भी प्रदान करता है। अपने प्रत्यक्ष योगदान के अलावा, सेवाएं विनिर्माण के "सेवाकरण" में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उत्पादन और परिवहन दोनों में उपयोग की जाने वाली सेवाओं के माध्यम से मूल्य बढ़ाती हैं।

त्वरित तथ्य: कर राजस्व रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जीएसटी संग्रह अप्रैल 2025 में चरम पर पहुंच जाएगा तथा वित्त वर्ष 26 के लिए कर-जीडीपी अनुपात 12% रहने का अनुमान है।



यह निरंतर गति सरकार के नेतृत्व में संरचनात्मक परिवर्तन का परिणाम है, जिसमें पारदर्शिता, व्यापार करने में आसानी और विनिर्माण, एमएसएमई, डिजिटल सेवाओं और बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता दी गई है।

बाहरी व्यापार: भारत के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार

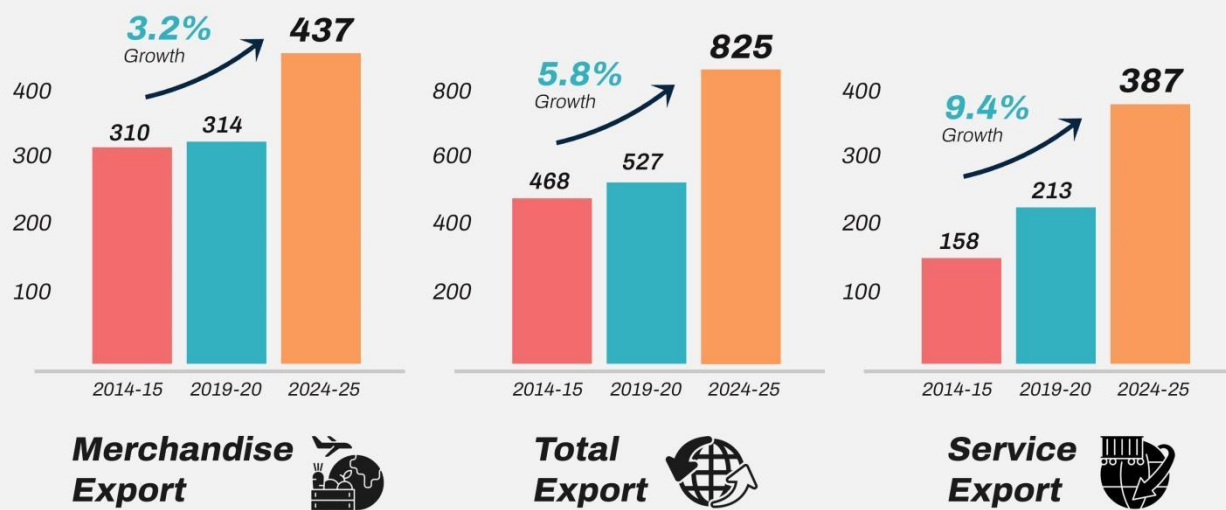
भारत के कुल निर्यात में पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2013-14 में 468 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 825 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो लगभग 76% की पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है।

इस वृद्धि को व्यापारिक निर्यात में मामूली वृद्धि से समर्थन मिला, जो पिछले वर्ष के 437.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में 437.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो माल-आधारित व्यापार में स्थिरता को दर्शाता है। दशक के दौरान, माल निर्यात 2013-14 में 310 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 437.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 39% की वृद्धि को दर्शाता है, जो इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों द्वारा संचालित है।

सेवाओं का निर्यात दोगुना से अधिक हो गया, जो 2013-14 में 158 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 387 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करता है।

Export Performance for 11 Years

India's Exports Value reached a milestone of more than US \$800 bn in 2024-25



Value in US\$ Billion
Period for CAGR (%)
2014-15 to 2024-25

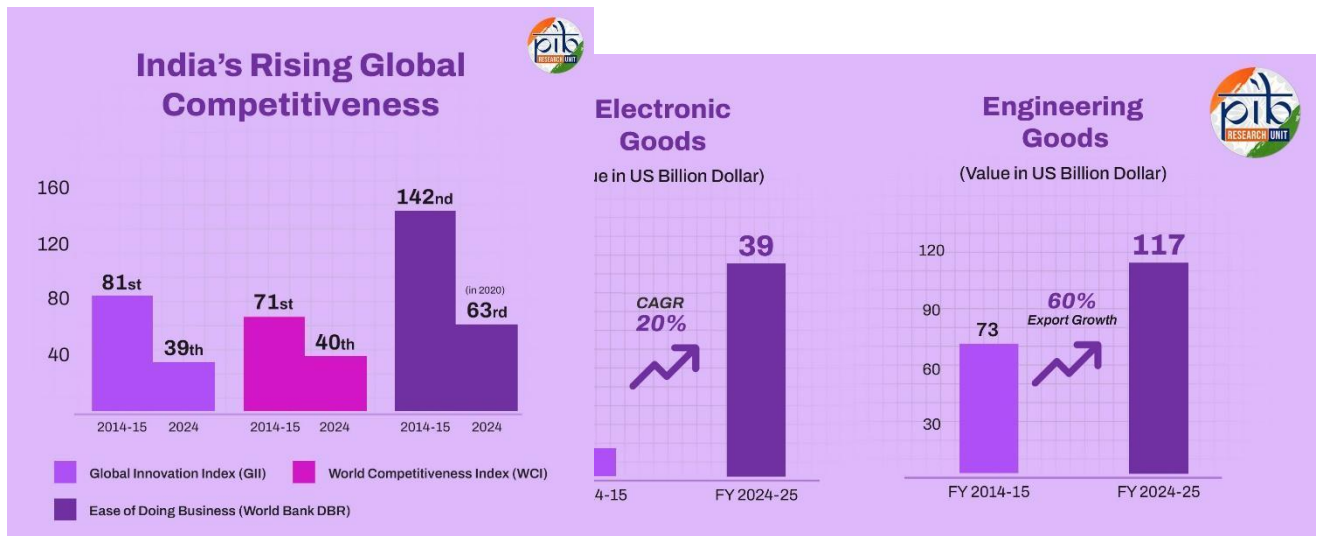
भारत के शीर्ष निर्यात क्षेत्र विकास गाथा की अगुआई कर रहे हैं

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में उछाल इसके शीर्ष तीन निर्यात क्षेत्रों- इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स- द्वारा प्रेरित किया गया है, जिन्होंने देश के व्यापार प्रदर्शन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

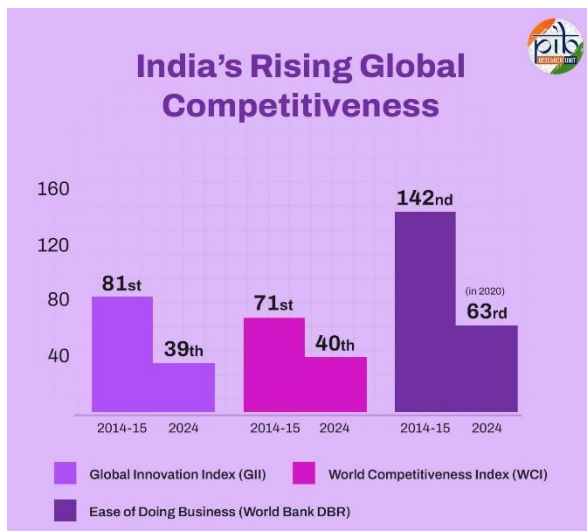
भारत का गैर-पेट्रोलियम निर्यात 374.1 बिलियन अमेरिका डॉलर (वित्त वर्ष 2024-25) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया

क्षेत्र	शीर्ष निर्यात गंतव्य	अन्य प्रमुख विशेषताएँ
---------	----------------------	-----------------------

इंजीनियरिंग सामान	यूएसए, यूएई, सऊदी अरब, यूके, जर्मनी	• सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक निर्यात मूल्य प्राप्त किया। • मेक इन इंडिया, ऑटो और कंपोनेंट्स के लिए पीएलआई योजना और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) कार्यक्रम जैसी प्रमुख पहलों द्वारा प्रेरित।
इंजीनियरिंग सामान	यूएई, यूएसए, नीदरलैंड, यूके, इटली	• क्षेत्र में 20% की सीएजीआर देखी गई। • मूल्य के संदर्भ में निर्यात वृद्धि: ~यूएस\$ 10 बिलियन
ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	200+ देश	• मात्रा के संदर्भ में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। • बाजार का 2030 तक यूएस\$ 130 बिलियन और 2047 तक यूएस\$ 450 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।



भारत में वैश्विक पूंजी प्रवाह



भारत तेजी से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए दुनिया के सबसे आकर्षक गंतव्यों में से एक बन गया है, जो एक दशक के संरचनात्मक सुधारों, निवेशक-अनुकूल नीतियों और बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता से प्रेरित है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग और रणनीतिक

पहलों में सुधार से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। सरकार अब वार्षिक एफडीआई प्रवाह को बढ़ाकर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखती है, जो कि मौजूदा पांच साल के औसत 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो बदलती आपूर्ति श्रृंखलाओं के बीच भारत को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों के अनुरूप है।

इन कारकों ने भारत में एफडीआई निवेश को बढ़ावा दिया है, अप्रैल 2000 और दिसंबर 2024 के बीच संचयी

प्रवाह 89.85 लाख करोड़ रुपये (यूएस \$ 1.05 ट्रिलियन) तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2001 से लगभग 20 गुना वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-दिसंबर 2024 के लिए भारत का एफडीआई इक्विटी प्रवाह 27% बढ़कर 3.40 लाख करोड़ रुपये (यूएस \$ 40.67 बिलियन) हो गया, जो मजबूत निवेशक विश्वास को दर्शाता है। यह वृद्धि प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई मानदंडों के उदारीकरण, जीएसटी की शुरुआत और मेक इन इंडिया पहल जैसे सुधारों से प्रेरित है।

क्षेत्र	संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह का हिस्सा (%)
सेवा	16.2%
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर	15.0%
व्यापार	6.4%
दूरसंचार	5.5%
ऑटोमोबाइल	5.2%

एफडीआई में प्रमुख उपलब्धियां

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह 84.84 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

- पिछले 10 वित्तीय वर्षों (2014-24) में एफडीआई प्रवाह 667.74 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। यह पिछले 24 वर्षों में दर्ज कुल एफडीआई (991.32 बिलियन अमरीकी डॉलर) का लगभग 67% है।
- एफडीआई में 26% की उछाल, वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में एफडीआई 42+ बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुँच गया
- 90% से अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह स्वचालित मार्ग के तहत प्राप्त हुआ।

वर्ग	मुख्य विशेषताएं
स्वास्थ्य सेवा एवं बीमा	• वित्त वर्ष 24 में अस्पताल क्षेत्र ने 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (12,708 करोड़ रुपये) आकर्षित किए, जो कुल स्वास्थ्य सेवा एफडीआई का 50% है। • बीमा क्षेत्र को नौ वर्षों में 6.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ। एफडीआई सीमा 26% (2014) से बढ़कर 74% (2021) हो गई।
अंतरिक्ष क्षेत्र	• मार्च 2024 में, पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई सुधारों को मंजूरी दी, जिससे निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए परिभाषित सीमाओं के तहत चयनित उपग्रह उप-क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति

वर्ग	मुख्य विशेषताएं
	मिली। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने वित्त वर्ष 24 के पहले नौ महीनों में 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जुटाए।
नवीकरणीय ऊर्जा	अप्रैल 2020 और सितंबर 2023 के बीच एफडीआई प्रवाह 6.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
रक्षा	- फरवरी 2024 तक रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 612 मिलियन अमेरिकी डॉलर (5,077 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया। ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ के तहत विदेशी ओईएम के साथ संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
खाद्य प्रसंस्करण	विश्व खाद्य भारत 2023 शिखर सम्मेलन में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (33,129 करोड़ रुपये) के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफपीआई और पीएमएफएमई जैसी योजनाओं के तहत 3.12 बिलियन

वर्ग	मुख्य विशेषताएं
	अमेरिकी डॉलर (25,869 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त निवेश जुटाया गया। .
टेक एवं ऑटो	• डेटाब्रिक्स 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2,133 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी और वित्त वर्ष 25 तक अपने कार्यबल का 50% विस्तार करेगी। • जनवरी 2024 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के पास बोइंग के 192.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1,600 करोड़ रुपये) के तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया। •
स्टार्टअप	उदार नीति और मजबूत निवेशक रुचि के समर्थन से भारत का अंतरिक्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम केवल 4 वर्षों में 1 से 190+ स्टार्टअप तक बढ़ गया। .

प्रमुख राज्य प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक निवेश आकर्षित कर रहे हैं

महाराष्ट्र	• 2030 तक 14% सीएजीआर पर जीडीपी को 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करके 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य।
------------	---

	हुंडई मोटर्स जीएम के तालेगांव प्लांट का अधिग्रहण करने के बाद 721.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर (6,000 करोड़ रुपये) का निवेश कर रही है।
कर्नाटक	एआई, स्वास्थ्य सेवा और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर (23,000 करोड़ रुपये) के 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए
गुजरात	- वाइब्रेंट गुजरात 2024 में, डीपी वर्ल्ड ने बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और एसईजेड के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (25,000 करोड़ रुपये) देने की प्रतिबद्धता जताई। - समझौता ज्ञापनों में डीप-ड्राफ्ट बंदरगाहों, माल ढुलाई गलियारों और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।

उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना



भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। इन योजनाओं ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि हुई है। उन्होंने घरेलू और विदेशी दोनों दावेदारों से महत्वपूर्ण निवेश भी आकर्षित किया है। पीएलआई योजनाओं ने भारत के निर्यात बास्केट को पारंपरिक वस्तुओं से उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार सामान, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों आदि में बदल दिया है। पीएलआई योजनाओं ने 5.31 लाख करोड़ रुपये (लगभग यूएस डॉलर 61.76 बिलियन) को पार कर लिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों जैसे क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है।

एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाना

6.3 करोड़ से अधिक उद्यमों के साथ, एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन और उद्यमिता में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार ने खादी, ग्राम और कॉयर उद्योगों सहित ऋण पहुँच, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास और बाज़ार समर्थन पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र का समर्थन किया है।

भुगतान में डिजिटल परिवर्तन

भारत ने डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह वृद्धि सरकारी पहलों, सहयोगी हितधारक प्रयासों और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढाँचे द्वारा सक्षम हुई है। इस परिवर्तन के केंद्र में एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) है, साथ ही तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और एनईटीसी फासटैग है, जिसने लेन-देन को

तेज़, सुरक्षित और अधिक सुलभ बना दिया है।

डिजिटल लेन-देन में क्रांति

भारत के डिजिटल भुगतान लेन-देन में तेजी से वृद्धि हुई है, जो व्यक्तियों और व्यापारों के बीच डिजिटल को अपनाने में तेजी को दर्शाता है।

● लेन-देन की मात्रा:

वित्त वर्ष 2017-18 में डिजिटल भुगतान लेन-देन 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 18,737 करोड़ हो गया, जिसने 44% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) हासिल की।

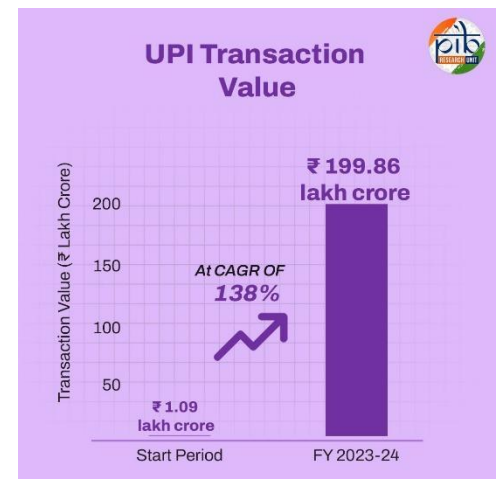
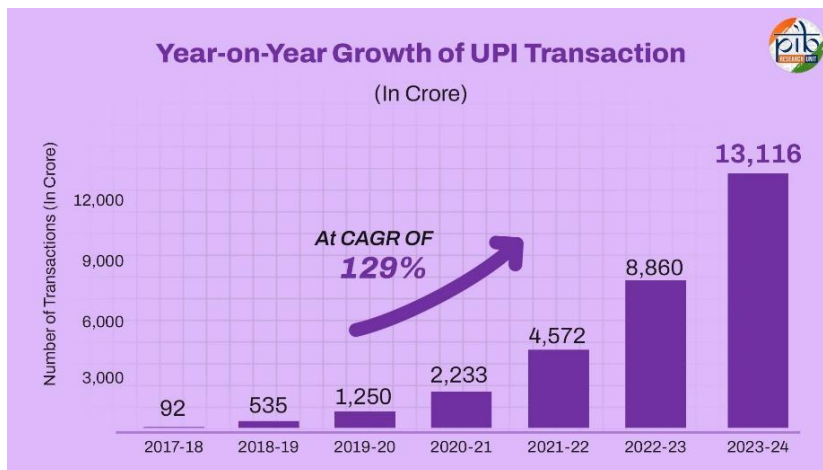
● लेन-देन मूल्य:

इसी अवधि में, लेन-देन का मूल्य 11% की सीएजीआर के साथ 1,962 लाख करोड़ से बढ़कर 3,659 लाख करोड़ रुपये हो गया।

यूपीआई: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक परिवर्तनकारी डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक मोबाइल एप्लिकेशन में एकीकृत करती है, जिससे सहज फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और मर्चेन्ट लेनदेन की सुविधा

मिलती है। इसने न केवल वित्तीय लेनदेन को तेज़, सुरक्षित और सरल बनाया है, बल्कि व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों को सशक्त बनाया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था कैशलेस हो गई है।



आईएमपीएस और एनईटीसी फासटैग : रियल-टाइम

और मोबिलिटी भुगतान को बढ़ाता है

जबकि यूपीआई मोबाइल-आधारित

पीयर-टू-पीयर और मर्चेन्ट भुगतानों पर

हावी है, तत्काल भुगतान सेवा

(आईएमपीएस) और एनईटीसी फासटैग

भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2010 में शुरू की गई आईएमपीएस एक वास्तविक समय, 24x7 इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण सेवा है जो मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और एसएमएस के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों में लेनदेन का समर्थन करती है

इसके साथ ही, भारत की डिजिटल टोल संग्रह प्रणाली, एनईटीसी फास्टैग सीधे लिंक किए गए बैंक खातों से कैशलेस टोल भुगतान को सक्षम बनाती है, जिससे यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ जाती है।

आईएमपीएस और फास्टैग साथ मिलकर पारंपरिक लेन-देन से परे डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने में सहायक हैं -

जिससे देश भर में निर्बाध फंड ट्रांसफर और मोबिलिटी से संबंधित भुगतान संभव हो रहे हैं।

डिजिटल भुगतान का अंतर्राष्ट्रीयकरण:

भारत के स्वदेशी रूप से विकसित यूपीआई और रुपये कार्ड डिजिटल भुगतान को सक्षम करने के लिए विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म हैं। सरकार इन उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। वर्तमान में यूपीआई

पूरी तरह से कार्यात्मक है और यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरीशस, फ्रांस और श्रीलंका में लाइव है। रुपये कार्ड की स्वीकृति यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर और मॉरीशस में लाइव है।

समावेशी विकास के मूलभूत अंग : भारत में वित्तीय सशक्तिकरण के 11 वर्ष

पिछले ग्यारह वर्षों में, भारत ने वित्तीय समावेशन को गहरा करने और जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2014 से शुरू की गई प्रमुख योजनाओं के एक समूह ने बैंकिंग, बीमा, पेंशन और ऋण तक पहुँच को काफी हद तक व्यापक बना दिया है। साथ में, उन्होंने एक अधिक लचीली, समावेशी और अवसर-संचालित अर्थव्यवस्था के लिए आधार तैयार किया है।

प्रधानमंत्री जन धन

योजना (पीएमजेडीवाई)

अगस्त 2014 में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई) के रूप में शुरू की गई पीएमजेडीवाई का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित विशाल आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नागरिक को अपनी वित्तीय गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का अवसर मिले। "बैंक रहित लोगों को बैंकिंग, असुरक्षित लोगों को सुरक्षित करना, अवित्तपोषित लोगों को वित्तपोषित करना और वंचितों तक लाभ पहुँचाना" के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित इस योजना ने पूरे देश में हर बैंकिंग सुविधा से वंचित परिवार को सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।



2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई)

2015 के केंद्रीय बजट में इस तथ्य के जवाब में घोषणा की गई थी कि केवल 20% भारतीयों के पास बीमा कवरेज है, पीएमजेबीवाई वार्षिक नवीकरणीय जीवन बीमा प्रदान करता है। 9 लाख से अधिक परिवारों को समय पर सहायता मिली है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सबसे प्रभावशाली सार्वजनिक जीवन बीमा योजनाओं में से एक बन गई है

3. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

9 मई 2015 को अपनी शुरुआत के बाद से, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) ने पूरे भारत में किफायती दुर्घटना बीमा कवरेज का विस्तार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

¹ <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2114011>

20 रुपये के मामूली वार्षिक प्रीमियम और आसान बैंक-लिंक्ड ऑटो-डेबिट नामांकन के साथ, पीएमएसबीवाई कमजोर वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

4. अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

असंगठित क्षेत्र में आयु जोखिम और सेवानिवृत्ति सुरक्षा की कमी से निपटने के लिए, एपीवाई को 2015 में लॉन्च किया गया था। यह योगदान और प्रवेश की आयु से जुड़ी एक परिभाषित मासिक पेंशन प्रदान करता है। अप्रैल 2025 तक, इस योजना में 7.65 करोड़ ग्राहक और कुल 45,974.67 करोड़ रुपये की राशि जमा हो चुकी है। अब सभी ग्राहकों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 48% है, जो महिला श्रमिकों के बीच बढ़ती वित्तीय जागरूकता और सुरक्षा का एक मजबूत संकेतक है।

5. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वित्तपोषित न होने वाले सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को वित्तपोषित करना है। संपार्थिक के बोझ को हटाकर और पहुँच को सरल बनाकर, मुद्रा ने जमीनी स्तर पर उद्यमिता के एक नए युग की नींव रखी। इस योजना ने पूरे भारत में शहरों से लेकर गाँवों तक उद्यमशीलता में बदलाव को बढ़ावा दिया है, जिससे नौकरी चाहने वाले नौकरी देने वाले बन गए हैं।

6. स्टैंड-अप इंडिया योजना

5 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के बाद से, स्टैंड-अप इंडिया

योजना ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को बैंक ऋण की सुविधा देकर ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाया है। इसने हजारों लोगों को व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने, आजीविका के अवसर पैदा करने और समावेशी आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने में सशक्त बनाया है।

7. पीएम विश्वकर्मा: भारत के पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाना



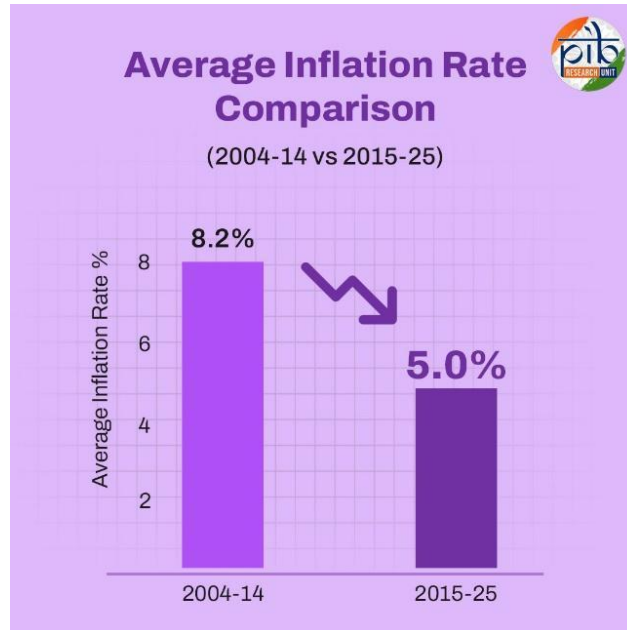
17 सितंबर, 2023 को शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य लोहार, बढई, कुम्हार, दर्जी, नाई, मोची और अन्य जैसे 18 पहचाने गए व्यवसायों में पारंपरिक

कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना है। यह योजना कौशल प्रशिक्षण, संपार्श्विक-मुक्त ऋण, आधुनिक टूलकिट, बाजार तक पहुंच और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन सहित समग्र समर्थन प्रदान करती है - इन कारीगरों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने में मदद करती है।

8. पीएम स्वनिधि योजना: किफायती ऋण के साथ स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून, 2020 को शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना और आर्थिक विकास के लिए उनके डिजिटल ऑनबोर्डिंग को बढ़ावा देना है। यह योजना तीन किस्तों में 50,000 रुपये तक के जमानत-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण, साथ ही 7% प्रति वर्ष ब्याज सब्सिडी और प्रति डिजिटल लेनदेन 1 रुपये का कैशबैक प्रोत्साहन (वार्षिक 1,200 रुपये तक) प्रदान करती है। प्रारंभ में 31 दिसंबर, 2024 तक वैध, यह योजना वर्तमान में विस्तार के अधीन है।

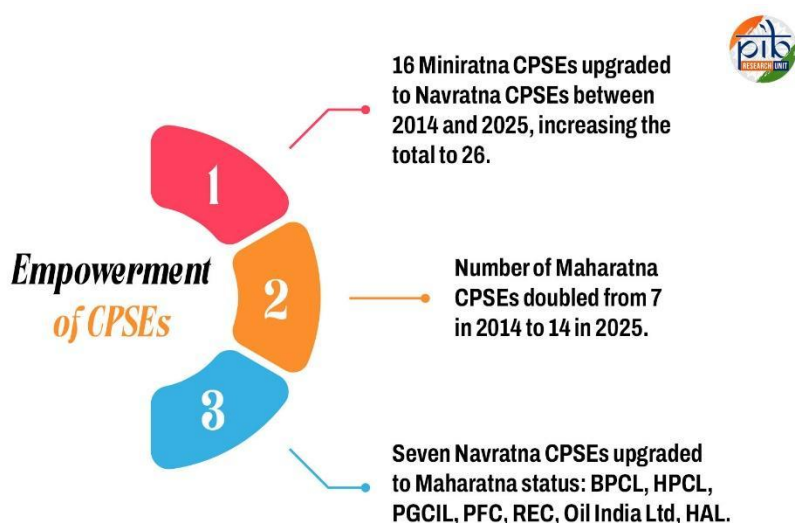
ऊँची कीमतों से स्थिरता तक: मुद्रास्फीति नियंत्रण का एक दशक पिछले दो दशकों में भारत ने अपने मुद्रास्फीति परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। 2004-05 और 2013-14 के बीच, मुद्रास्फीति औसतन 8.2% रही, जिसमें कई वर्षों तक दोहरे अंकों में वृद्धि देखी गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें थीं। इस अवधि ने घरेलू बजट पर दबाव डाला और व्यवसायों के लिए अनिश्चितता पैदा की।



हालांकि, 2015-16 से 2024-25 तक, मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है और यह औसतन लगभग 5% पर आ गई है। यह बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और सरकार द्वारा सुदृढ़ राजकोषीय अनुशासन सहित मजबूत नीतिगत हस्तक्षेपों को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, मूल्य स्थिरता में सुधार हुआ है, जिससे उपभोक्ता विश्वास बढ़ा है और सतत आर्थिक विकास को समर्थन मिला है।

सीपीएसई: भारत के आर्थिक परिवर्तन के उत्प्रेरक

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रणनीतिक राष्ट्रीय



परिसंपत्तियों के रूप में, वे केवल वाणिज्यिक संस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय विकास के स्तंभ हैं, जो नमक, चाय और कागज जैसे रोजमर्रा के घरेलू उत्पादों से लेकर भारी मशीनरी, इलेक्ट्रिक वाहनों और राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले घटकों तक - व्यापक स्पेक्ट्रम में आवश्यक बुनियादी ढाँचा, विनिर्माण क्षमताएँ और सेवाएँ प्रदान करते हैं।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रमुख उपलब्धियाँ:

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) ने पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सूचक	2014 (वित्त वर्ष 14/16)	2024 (या वित्त वर्ष 24/25)	वृद्धि
प्रदत्त पूंजी कुल राजस्व	2 लाख करोड़ रुपये	6 लाख करोड़ रुपये	↑ 199%
कुल राजस्व	21 लाख करोड़	36 लाख करोड़	↑ 75%

सूचक	2014 (वित्त वर्ष 14/16)	2024 (या वित्त वर्ष 24/25)	वृद्धि
	रुपये	रुपये	
शुद्ध लाभ (संचालित सीपीएसई)	1.3 लाख करोड़ रुपये	3.2 लाख करोड़ रुपये	↑ 149%
लाभ (लाभ कमाने वाले सीपीएसई)	1.5 लाख करोड़ रुपये	3.4 लाख करोड़ रुपये	↑ 130%
केन्द्रीय राजकोष में योगदान	2.2 लाख करोड़ रुपये	4.9 लाख करोड़ रुपये	↑ 120%
निवल मूल्य	9. लाख करोड़ रुपये	20 लाख करोड़ रुपये	↑ 110%
व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	17.5 लाख करोड़ रुपये	43 लाख करोड़ रुपये	↑ 145%
पूंजीगत व्यय (सीपीएसई)	1.9 लाख करोड़ रुपये	₹3.3 लाख करोड़ रुपये	↑ 74%
संयुक्त पूंजी व्यय (सीपीएसई + रेलवे + एनएचएआई)	3.1 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 16)	8.1 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 25)	↑ 161%

निष्कर्ष

पिछले दशक में, भारत ने संरचनात्मक सुधारों, दूरदर्शी नीति निर्माण और अटूट राजनीतिक इच्छाशक्ति पर आधारित एक गहन आर्थिक परिवर्तन किया है। ऐतिहासिक जीडीपी वृद्धि और रिकॉर्ड निर्यात हासिल करने से लेकर डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने और वित्तीय समावेशन के माध्यम से लाखों लोगों को सशक्त बनाने तक, देश ने एक लचीली, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था की नींव रखी है। मजबूत एफडीआई प्रवाह, व्यापार का विस्तार और नवाचार-संचालित क्षेत्रों के नेतृत्व में, भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक निष्क्रिय भागीदार न होकर, अपने भविष्य का एक प्रमुख वास्तुकार है। जैसा कि देश शीर्ष तीन आर्थिक शक्ति बनने के अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, पिछले ग्यारह वर्षों की गति संकेत देती है कि भारत का आर्थिक उदय केवल एक अवसर नहीं - आंदोलन है।

संदर्भ:

- वित्तीय सेवा विभाग।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
 - <https://www.pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NotelId=153288&ModuleId=2>
 - <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2106921#:~:text=%5BPrimary%20Sector:%20Agriculture%2C%20Live%20stock,Administration%2C%20Defence%20&%20Other%20Services%5D>
 - <https://www.indiabudget.gov.in/budget2015-2016/es2014-15/echapter-vol2.pdf>
 - <https://www.indiabudget.gov.in/budget2015-2016/es2014-15/echapvol2-01.pdf#:~:text=It%20is%20observed%20that%20the%20contribution%20of,2.6%20per%20cent%20and%20from%2022.1%20p>

er

- <https://www.mospi.gov.in/percentage-share-gross-value-added-different-economic-sector-2011-12-2023-24-sae-base-year-2011-12-0>
- <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/feb/doc202521494001.pdf>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2122016>
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153223&ModuleId=3>
- <https://www.ibef.org/economy/foreign-direct-investment>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2083683>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2122148>
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154428&ModuleId=3>
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154426&ModuleId=3>
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154432&ModuleId=3>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119954>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119045>

Explainer 15/ Series on 11 Years of Government

Santosh Kumar/ Ritu Kataria/ Anchal Patiyal